

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

03/2018
05.01.2018

प्रधान पुत्र हरपाल जाति मीना निवासी रोशनपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला—टोंक

—रेस्पोंडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सोप दिनांक 18.09.2017 मिसल नम्बर 243/2017

- उपस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय. परोकार

निर्णय

दिनांक 12.09.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 18.09.2017 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 178 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु०रास्ता वाके ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर वाडा बनाकर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से वेदखल करने, 1000/रु. पेनल्टी कायम कर 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिल्लाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की वहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विना सुने व विना साक्ष्य सवूत पेश करने का अवसर प्रदान किये विना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट नही मंगवाई गई है और ना ही स्वयं द्वारा मौका देखा गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलांट के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का किसी भी प्रकार से उक्त भूमि पर अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने वावत कोई साक्ष्य—सवूत भी नही है। अपीलांट को उक्त भूमि



जिला कलेक्टर
टोंक

से वास्तविक रूप से कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्त के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्त को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 178 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा बनाने पर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सोप द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्त भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्त की स्वयं की तामील हुई है। अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्त द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 178 रकबा 0.01 है० किस्म गै०मु० रास्ता वाके ग्राम रोशनपुरा तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर बाडा बनाकर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्त ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं० 68/2016 निर्णय दिनांक 27.09.2016 से भूमि से बेदखल किया गया है। नायब तहसीलदार सोप ने उनके पत्र क्रमांक 300 दिनांक 02.08.2022 से अवगत करवाया है कि वर्तमान में उक्त भूमि पर अपीलांत का अतिक्रमण नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप का निर्णय दिनांक 18.09.2017 इस शर्त के साथ अपास्त किया जाता है कि यदि अपीलान्त पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



वि-अ-अ
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर, टोक